



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2012/ज्येष्ठ 15, 1934
DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2012/JYAISTHA 15, 1934

[रा.ग.रा.क्षे.दि. सं. 55
[N.C.T.D. No. 55]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 जून, 2012

सं. 21(12)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4313.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (12) 2012]

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 05 जून, 2012 को पुरस्थापित किया गया)

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 में आगे संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रांरभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाए।
(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
(3) यह उस तारीख से प्रभावी होगा जो तारीख सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. धारा 2 का संशोधन:—विलासिता कर अधिनियम, 1996 में (इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” के रूप में संर्भित), की धारा 2 में—
(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—
“(कक) “बैन्कट हॉल” का अर्थ है ऐसा कोई परिसर, बगीचा या फार्म हाउस या उसका कोई भाग जहाँ आवास या स्थल, विवाह,

रिसेप्शन या उससे संबंधित समारोह, सेमीनार, संगोष्ठी, दावत, पार्टी, बैठक या प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया हो तथा ऐसा अन्य हॉल जो आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किया गया हो, इस तथ्य का ध्यान रखे बिना कि चाहे वह नियमित हो या आवधिक या यदा-कदा के आधार पर हो;";

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "व्यापार" में मौद्रिक प्रतिफल के लिए किसी प्रकार की विलासिता तथा उससे संबंधित या आनुवंशिक या प्रासंगिक के संदर्भ में कोई विलासिता उपलब्ध कराना शामिल है;";

(iii) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड.) "रियायती दर" किसी होटल में उपलब्ध कराई गई विलासिता के संदर्भ में रियायती दर का अर्थ है स्वामी द्वारा ऐसी विलासिता के लिए नियत सामान्य दर से कम दर या तत्समय लागू सरकार, प्रधिकरण या विधि के अधीन नियत से कम दर;";

(iv) खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड.क) "उपभोक्ता" का अर्थ है व्यक्तिगत या समूह या कंपनी अथवा कॉर्पोरेट जो विलासिता का उपयोग कर रहा है;

"(ड.ख) "स्थापना" का अर्थ है कोई बैंकट हॉल या व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब या होटल या कोई स्पा जहाँ किसी उपभोक्ता को व्यापार के द्वारा विलासिता उपलब्ध कराई जाती है;";

(v) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चक) "व्यायामशाला या स्वास्थ्य क्लब" का अर्थ है, अच्छी सेहत, एरोबिक्स या बॉडी बिल्डिंग या शरीर सज्जा इत्यादि जैसी सुविधाएं और गतिविधियां उपलब्ध कराने के लिए जिम अथवा अन्य शारीरिक व्यायाम उपकरणों के लिए परिसर, हॉल, भवन या उपकरणों से सुसज्जित कोई स्थान;";

(vi) खंड (ज) को हटाया जाएगा;

(vii) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झ) "विलासिता" का अर्थ है किसी उपभोक्ता द्वारा जीवन की आवश्यकता के लिए असाधारण रूप से किसी उपभोक्ता द्वारा मनोरंजन या सुविधा या प्रसन्नता या उपभोग के लिए वस्तुएं, सेवाएं, संपत्ति सुविधाएं इत्यादि का प्रयोग, अर्थात् :—

(i) किसी बैंकट हॉल में उपलब्ध कराया गया कोई आवास या स्थल जिसमें ठंडी हवा, वातानुकूलन, कूर्सियों, मेज, लिनन, बर्टन तथा पात्र, शामियाना, टेंट, पैवेलियन, बिजली, पानी, ईंधन, आन्तरिक या बाह्य सज्जा, संगीत, ऑरकेस्ट्रा, सीधा प्रसारण और इसी तरह की अन्य सुविधा सम्मिलित है;

(ii) व्यायामशाला या स्वास्थ्य क्लब में उपलब्ध सेवाएं जिसमें प्रशिक्षक अथवा व्यक्तिगत प्रशिक्षक की सेवा, स्टीम, सॉना तथा इसी तरह की अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं;

(iii) किसी होटल में आवास तथा अन्य सेवाएं, जिसके लिए दर या प्रभार में ठंडी हवा, वातानुकूलन, रेडियो, संगीत, अतिरिक्त बिस्तरे, दूरदर्शन तथा इसी तरह की अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, सात सौ पचास रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन या अधिक हो, चाहे ऐसा प्रभार एकत्रित रूप से या अलग-अलग रूप से प्रति कक्ष प्रतिदिन प्राप्त किया गया हो;

(iv) किसी स्पा में उपलब्ध सुविधाएं या सेवाएं जिसमें सौन्दर्य उपचार, मैनीक्योर, पैडीक्योर, फेसियल, लेजर उपचार, मालिश, शॉवर, जल चिकित्सा, भाप स्नान, सॉना अथवा व्यंजन, मैडीस्पा तथा इसी तरह की अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं;";

(viii) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) "स्वामी" का अर्थ है किसी स्थापना का संयुक्त या पृथक रूप से मालिक तथा इसमें साझेदार, प्रबंधन, न्यास, कंपनी, फर्म या कोई भी सम्मिलित है, जो कि तत्समय स्थापना के प्रबंधन का प्रभारी हो;";

(ix) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) "प्राप्ति" का अर्थ है स्थापना में उपलब्ध कराई गई किसी विलासिता के लिए किसी स्वामी अथवा उसके एजेंट द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने योग्य मौद्रिक प्रतिफल की राशि;";

(x) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ढ) "पंजीकृत स्वामी" का अर्थ है, इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत स्वामी;";

(xi) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ण क) "स्पा" का अर्थ है कि कोई भवन या उसका कोई भाग या स्थान जहाँ पर सौन्दर्य उपचार अथवा मैनीक्योर या पैडीक्योर या फेसियल या लेजर उपचार या मालिश या शॉवर या जल चिकित्सा या भाप स्नान, सॉना या व्यंजन या मैडीस्पा या

इसी तरह की अन्य सेवाएं उपलब्ध हो;";

(xii) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(त) "कर" का अर्थ है, किसी स्थापना में प्राप्तियों की सकल बिक्री पर वसूला गया या वसूली योग्य कर तथा इस अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर जिसमें कोई अर्थदंड, ब्याज, दंड, समाधान राशि, जब्त की गई राशि या इस अधिनियम के अधीन वसूला गया या वसूली योग्य अन्य कोई प्रभार;";

(xiii) खंड (थ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(थ) "प्रभार" का अर्थ है विलासिता उपलब्ध कराने के लिए किसी स्वामी द्वारा वसूला गया या वसूली योग्य प्रभार;";

(xiv) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(द) "प्राप्तियों की सकल बिक्री" का अर्थ है विलासिता के संबंध में स्वामी द्वारा वसूल किया गया अथवा वसूली योग्य मूल्य योग्य प्रतिफल की सकल राशि;";

3. धारा 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. कर की वसूली और विस्तार (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार प्रत्येक स्वामी, जो—

(क) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो, अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाना अपेक्षित हो;

इस अधिनियम के उपबंधित समय तथा पद्धति से इस अधिनियम के अनुसार परिकलित प्राप्तियों की अपनी सकल बिक्रियों पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) उस दर पर स्वामी की प्राप्तियों की कुल बिक्री पर कर वसूला जाएगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने के लिए पन्द्रह प्रतिशत से अधिक न हो तथा विलासिताओं की विभिन्न श्रेणी के लिए विभिन्न दरों अधिसूचित की जा सकती है :—

उपबंध है कि जहाँ दैनिक आधार या प्रति कक्ष आधार पर अन्यथा प्रभार वसूला जाता है तब इस आधार के अधीन कर देयता निश्चित करने के लिए प्रभार आवास के अधिभोग की कुल अवधि पर आधारित एक दिन के लिए तथा प्रतिकक्ष अनुपातिक रूप से परिकलित होगा जिसके लिए होटल के नियमों तथा पद्धति के अनुसार प्रभार लिया जाएगा ।

(3) यदि विलासिता उपलब्ध कराने के लिए प्रभारों के अतिरिक्त सेवा प्रभार वसूला जाता है तथा स्वामी द्वारा विनियुक्त किया जाता है तथा स्टाफ को भुगतान नहीं किया जाता है तब ऐसे प्रभारों को इस अधिनियम के अधीन कर की वसूली के उद्देश्य के लिए प्राप्तियों की कुल बिक्री का भाग समझा जाएगा ।

(4) यदि किसी व्यक्ति को होटल में दी गई विलासिता (जो स्वामी का कर्मचारी न हो) का प्रभार बिल्कुल नहीं वसूला जाता या रियायती दर पर प्रभारित किया जाता है, निसन्देह उस विलासिता पर उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी विलासिता पर कर वसूला और एकत्रित किया जाएगा, माना ऐसी विलासिता के लिए पूरा प्रभार स्वामी को भुगतान किया गया था ।

(5) खाद्यान्न, पेय पदार्थों तथा वस्तुओं जैसे सौन्दर्य प्रसाधन, औषधियां, पौष्टिक पूरक आहार इत्यादि की आपूर्ति के लिए प्राप्तियों की कुल बिक्री के संबंध में कर नहीं लगाया जाएगा और भुगतान योग्य नहीं होगा, जिसकी बिक्री पर स्वामी, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है ।

(6) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए स्वामी द्वारा पृथक रूप से एकत्रित कर प्राप्ति या प्राप्तियों की सकल बिक्री के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा ।"

4. धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) को उप-धारा (7) के रूप में पुनः सांख्यांकित किया जाएगा, निम्नलिखित उप-धारा, उप-धारा (1) के रूप में सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक स्वामी जिसकी किसी प्रकार की विलासिता उपलब्ध कराने तथा उसके आनुषंगिक प्रभारों के लिए किसी वर्ष के प्रारंभ होने से परिकलित प्राप्तियों की कुल बिक्री निम्नानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक होती है, को अगले दिन से ही उसे इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाना आवश्यक होगा :—

क्र. सं.	विलासिता कर	प्रारंभिक मूल्य (रुपये में)
1.	बैंकट हाल सुविधाएं	पाँच लाख
2.	व्यायामशाला/स्वास्थ्य क्लब	पाँच लाख
3.	प्रतिदिन प्रतिकक्ष 750 रुपये या इससे अधिक प्रभार सहित होटल आवास	शून्य
4.	स्पा	पाँच लाख

उपर्युक्त है किसी स्वामी के होटल में आवास का प्रभार एक हजार या इससे अधिक प्रतिकक्ष प्रतिदिन है तथा जिसकी पिछले वर्ष कुल बिक्री या दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ होने के वर्ष में प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व, कुल बिक्री उपरोक्त विनियिदित प्रारंभिक मूल्य से अधिक है, वह उपरोक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पंजीकरण कराने का उत्तरदायी होगा।

5. शब्द “होटल” का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 2, धारा 3 और धारा 8 की उप-धारा (1) को छोड़कर इसमें आए शब्द “होटल”, कोई होटलों तथा “होटल” जहां कहीं ये शब्द आते हैं, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द “स्थापना” “कोई स्थापना” तथा “स्थापना एं” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. शब्द “होटलियर” का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 2, धारा 3 एवं धारा 8 की उप-धारा (1) को छोड़कर जहां कहीं शब्द “होटलियर” आता है, उसके स्थान पर शब्द “स्वामी” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

प्रस्तावित संशोधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—

- (i) नए क्षेत्रों के समावेशन द्वारा कर संरचना का आधार व्यापक बनाना—पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह पाया गया है कि कुछ विलासिता एं जैसी किसी बैंकट हॉल, व्यायामशाला/हैल्थ क्लबों, स्पा जैसी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो इनकी प्रकृति को देखते हुए अधिनियम के दायरे के अन्तर्गत लाई जानी चाहिए, चूंकि ये सेवाएं/सुविधाएं समाज के सम्पन्न वर्ग द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इसके अतिरिक्त 22-6-2009 से विलासिता कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और विलासिता कर की लेवी के प्रयोजनार्थ 20-9-2010 से 500 रुपये की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 1000 रुपये करने के परिणामस्वरूप विलासिता कर के संग्रहण में भारी कमी आई है, जिसका वार्षिक आधार पर विलासिता कर की वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। विलासिता कर का आधार पुनः बढ़ाने के लिये यह भी महसूस किया गया है कि किसी होटल में 750 रुपये या अधिक भाड़ प्रतिदिन लेकिन 1000 रुपये प्रतिदिन से कम विलासिता कर नेट के अन्तर्गत भी लाना चाहिए।
- (ii) अधिक राजस्व का सूजन—उक्त वर्णित बैंकट हॉलों व्यायामशालाओं, स्वास्थ्य और स्पॉज जैसे नए क्षेत्रों का समावेशन जो पहले कभी भी विलासिता कर की बसूली के लिए काम में नहीं लाए गए हैं, ये विलासिता कर की समग्र वृद्धि के लिये नए स्रोत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हैं, जो वार्षिक आधार पर सरकार द्वारा निश्चित विलासिता कर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये विभाग को समर्थ बनाएगा। उक्त वर्णित विधायी संशोधन प्रशासनिक सुधारों और प्रवर्तन और सतर्कता पर ध्यान देकर पूरे किए जाएंगे।

एक और तो प्रस्तावित संशोधन कराधान के गतिशील प्रक्रम को प्रारंभ करेंगे और दूसरी और राज्य के कार्यकलापों को और विकासशील गतिविधियों को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त संसाधनों का सूजन करेंगे। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि आबकारी, मनोरंजन कर और विलासिता कर विभाग राजस्व के मामले में तीसरा सबसे बड़ा धन अर्जित करने वाला विभाग है और कर आधार का विस्तार करके यह स्थिति बनाई रखनी अपेक्षित है। प्रस्तावित संशोधनों से पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है।

शीला दीक्षित,
वित्त मंत्री

नई दिल्ली

दिनांक : 5-6-2012

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) विधेयक, 2012 में उल्लिखित प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से यथोच्च व्यय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आधिक सहायता अपेक्षित नहीं होगी।

गौण विधान के लिये ज्ञापन

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 में संशोधन के वर्तमान प्रस्ताव गौण/अधीनस्थ विधान के लिये शक्ति सौंपने के लिये विचार नहीं करते हैं। तथापि दिल्ली विलासिता कर नियमावली, 1996 के सम्बद्ध उपबंधों के क्रियान्वयन, संशोधनों के लिये विद्यमान प्रत्यायोजन के अन्तर्गत अपेक्षित होगा।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th June, 2012

No. 21(12)/2012/LAS-IV/Leg./4313.—The following is published for general information.—

THE DELHI TAX ON LUXURIES (AMENDMENT) BILL, 2012

(Bill No. 12 of 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 5th June, 2012)

A Bill further to amend Delhi Tax on Luxuries Act, 1996.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.— In the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 2,—

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

"(aa) "banquet hall" means any premises, garden or farm house, or any part thereof where accommodation or space is provided for marriage, reception or functions related therewith, seminar, convention, banquets, party meeting, or exhibition-cum-sale and such other hall as may be specified by the Commissioner, irrespective of the fact whether on regular or periodical or occasional basis;";

(ii) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) "business" includes activity of providing any luxury and any other service in connection with, or incidental or ancillary for monetary consideration;" ;

(iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

"(e) "concessional rate" in relation to a luxury provided in a hotel, means a rate lower than the normal rate fixed for such luxury by the proprietor or lower than that fixed by any Government, authority or under law for the time being in force;" ;

(iv) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(ea) "customer" means an individual or group or company or corporate availing any luxury; "

"(eb) "establishment" means a banquet hall or a gymnasium/health club or a hotel or a spa where luxury is provided to a customer by way of business;" ;

(v) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(fa) "gymnasium or health club" means a premises or hall or building or place equipped for gymnastics and other physical exercising equipment(s) for providing facilities and activities such as wellness, aerobics or body building or body sculpting etc;" ;

(vi) the clause (h) shall be omitted;

(vii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) "luxury" means use of goods, services, property, facilities etc. for enjoyment or comfort or pleasure or consumption by any customer extraordinary to the necessity of life, that is to say :—

(i) accommodation or space provided in a banquet hall which includes air cooling, air conditioning, chairs, tables, linen, utensils and vessels, shamiyana, tent, pavilion, electricity, water, fuel, interior or exterior decoration, music, orchestra, live telecast and the like;

(ii) services provided in a gymnasium or health club, which includes services of trainer or personal trainer, steam, sauna and the like;

(iii) accommodation and other services provided in a hotel, the rate or charges for which, including the charges for air cooling, air conditioning, radio, music, extra beds, television and the like, is seven hundred fifty rupees per room per day or more, whether such charges are received collectively or separately per room per day;

- (iv) facilities or services provided in a spa which includes beauty treatment, manicure, pedicure, facial, laser, treatment, massage shower, hydrotherapy, steam bath, saunas or cuisine, medispa and the like;”;
- (viii) after clause (l), the following clause shall be inserted, namely :—
“(la) “proprietor” means the owner of an establishment, jointly or severally, and includes partners, management, trust, company, firm or anybody who is for the time being in charge of the management of the establishment;”;
- (ix) for clause (m), the following clause shall be substituted, namely :—
“(m) “receipt” means the amount of monetary consideration received or receivable by a proprietor or by his agent for any luxury provided in the establishment;”;
- (x) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely :—
“(n) “registered proprietor” means a proprietor registered under section 8 of this Act;”;
- (xi) after clause (o), the following clause shall be inserted, namely :—
“(oa) “spa” means a building or part of building or space where facilities or services for beauty treatment or manicure or pedicure or facials or laser treatment or massage or shower or hydrotherapy or steam bath or saunas or cuisine or medispa or the like is provided;”;
- (xii) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely :—
“(p) “tax” means the tax levied or leviable on turnover of receipts of an establishment and payable under this Act including any penalty, interest, fine, composition money, sum forfeited or any other charge levied or leviable under this Act;”;
- (xiii) for clause (q), the following clause shall be substituted, namely :—
“(q) “tariff” means the charges levied or leviable by a proprietor for providing any luxury;”;
- (xiv) for clause (r), the following clause shall be substituted, namely :—
“(r) “turnover of receipt” means the aggregate of amount of valuable consideration received or receivable by a proprietor in respect of any luxury;”;

3. Amendment of section 3.—In the principal Act, for Section 3, the following shall be substituted, namely :—

“3. Incidence and levy of tax.”—(1) Subject to other provisions of this Act, every proprietor,—

- (a) registered under this Act; or
- (b) required to be registered under this Act;

shall be liable to pay tax on his turnover of receipts calculated in accordance with this Act, at the time and in the manner provided in this Act.

(2) There shall be levied a tax on the turnover of the receipts of a proprietor at a rate not exceeding fifteen per cent to be notified by the Government from time to time and different rates may be notified for different class of luxuries:

Provided that, where the charges are levied otherwise than on daily basis or per room then the charges for determining the tax liability under this Section shall be computed proportionately for a day and per room based on the total period of occupation of the accommodation for which the charges are made according to rules or practice of the hotel.

(3) In case, in addition to the charges for providing luxury, service charges are levied and appropriated by the proprietor and not paid to the staff, then, such charges shall be deemed to be part of the turnover of receipts for the purpose of levy of tax under this Act.

(4) In case luxury provided in a hotel to any person (not being an employee of the proprietor) is not charged at all, or is charged at a concessional rate, nevertheless there shall be levied and collected the tax on such luxury, at the rate specified in sub-section (2), as if full charges for such luxury were paid to the proprietor.

(5) The tax shall not be levied and payable in respect of turnover of receipts for supply of food, drinks and goods such as cosmetics, medicines, nutritional supplements etc. on the sale of which the proprietor is liable to pay tax under the Delhi Value Added Tax Act, 2005.

(6) For the purposes of this Act, tax collected separately by the proprietor shall not be considered to be part of the receipt or the turnover of receipts of the proprietor.”

4. Amendment of section 8.—In the principal Act, in section 8, sub-section (1) shall be renumbered as sub-section (7), the following sub-section shall be inserted as sub-section (1), namely :—

"(1) Every proprietor whose turnover of receipts for providing any luxury and charges incidental thereto, calculated from the commencement of any year first exceeds, within such year the threshold value as specified below, against the respective luxury, shall, from the very next day, be required to get himself registered under this Act:

S. No.	Luxury	Threshold Value (in rupees)
1.	Banquet Hall facilities	five lac
2.	Gymnasium/Health Club	five lac
3.	Hotel accommodation with tariff Rs. 750 per day per room or more	nil
4.	Spa	five lac

Provided that a proprietor, who is engaged in business of providing any luxury, other than that of accommodation in a hotel having tariff of rupees one thousand or more room per day, and whose turnover in the previous year or in the year of commencement of the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2012 before the date of commencement, exceeds the threshold values specified above shall be liable for registration from the date of commencement of the aforesaid Act.

5. Substitution of the word "hotel".—In the principal Act, for the words "hotel", "a hotel" and "hotels" wherever they occur, except in section 2, section 3 and sub-section (1) of section 8, the words "establishment", "an establishment" and "establishments" shall be substituted, respectively.

6. Substitution of the word "hotelier".—In the principal Act, for the word "hotelier", wherever it occurs, except in section 2, section 3 and sub-section (1) of section 8, the word "proprietor" shall be substituted.

Statement of Objects and Reasons

The proposed amendments are aimed at the following :—

- (i) Board basing the tax structure by inclusion of new areas—It has been observed during the last few years that there are some luxuries like service and facilities provided in a banquet halls, gymnasiums/health clubs, spas, which should have been brought under the ambit of the Act keeping in view their very nature, as these services are availed by the affluent strata of the society. Moreover, the reduction in the rate of luxury tax from 12.5% to 10% w.e.f. 22-6-2009 and raising the threshold limit from Rs. 500 to Rs. 1000 w.e.f. 20-9-2010 for the purpose of levy of luxury tax has caused considerable reduction in collection of luxury tax which had an adverse impact on the rate of growth of luxury tax on annual basis. In order to augment the luxury tax base further, it is also felt that the rooms provided by way of accommodation, against a tariff of Rs. 750 per day or more but below Rs. 1000 per day in a hotel should also be brought under the luxury tax net.
- (ii) Greater revenue generation—The inclusion of new areas like banquet halls, gymnasiums/health clubs, and spas as cited above which have never been tapped previously for realization of luxury tax are bound to provide fresh impetus to the overall growth of luxury tax, which would enable the Department to achieve the luxury tax target fixed by the Government on annual basis. The above said legislative amendments would be supplemented by way administrative reforms and focus on enforcement and vigilance.

The proposed amendments on the one hand will initiate a dynamic process of taxation which would be progressive and on the other hand will aim at generating additional resources for running the affairs of the STATE and for carrying out developmental activity. It is worth mentioning here that Excise, Entertainment Tax and Luxury Tax Departments is the third highest earner in terms of revenue and this position is required to be sustained by expansion of tax base. Proposed amendments are aimed at achieving the aforesaid objectives.

SHEILA DIXIT, Minister of Finance

New Delhi

Dated : 5-6-2012

FINANCIAL MEMORANDUM

For the implementation of the proposals contained in the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Bill, 2012, no additional financial assistance will be required from Central Government through substantive expenditure from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi.

MEMORANDUM FOR SUB-ORDINATE LEGISLATION:

The present proposal of amendment in the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 does not envisage delegation of power for sub-ordinate legislation. However, for implementation, amendments of relevant provision of Delhi Tax on Luxuries Rules, 1996 would be required under existing delegation.

सं. 21(11)/2012/एलएएस-IV/एलईजी/4309.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2012

[विधेयक संख्या (11) 2012]

(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 05 जून, 2012 को पुरास्थापित किया गया)

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 का पुनः संशोधन करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह उस तारीख से लागू होगा जैसा सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन:—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके बाद "मूल्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (य घ) में उप-खंड (vii) के पश्चात्, इसके अन्त में आई व्याख्या से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

"शर्त यह है कि 3 जून, 2012 से प्रभावी होने वाले पैट्रोल के मूल्य (केन्द्र सरकार द्वारा उस पर बसूले कर एवं लैबी सहित) में वृद्धि शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश देती है या यदि पैट्रोल का मूल्य 3 जून, 2012 से पहले के विक्रय मूल्य से कम हो जाता है, जो भी पहले हो, बैचे गए पैट्रोल के विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगा :

आगे शर्त यह है कि यदि पैट्रोल का मूल्य 3 जून, 2012 को प्रचलित मूल्य से अधिक पुनः बढ़ता है तो पूर्वोक्त परन्तुक पर इस प्रकार की आगामी वृद्धि का कोई प्रभावी नहीं पड़ेगा :

आगे यह भी शर्त है कि यदि पैट्रोल के मूल्य में गिरावट आती है लेकिन 3 जून, 2012 से पूर्व प्रचलित मूल्य से अधिक रहता है, तो पूर्वोक्त परन्तुक का शेष बढ़ोत्तरी की सीमा तक प्रभाव पड़ेगा :

शर्त यह भी है कि उपरोक्ताओं तक लाभ पहुंचने तक पूर्वोक्त परन्तुक का प्रभाव नहीं होगा।"

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 की धारा 2, दिनांक 3 जून, 2012 से बढ़ी पैट्रोल की कीमतों पर वैट की लैबी से हूट के माध्यम से पैट्रोल की अधिक बढ़ी कीमतों से आम जनता को राहत देने का प्रस्ताव करती है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

शीला दीक्षित, मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री

नई दिल्ली

दिनांक :

वित्तीय ज्ञापन

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2012 में किसी प्रकार की वित्तीय जटिलताएं सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से नए पदों पर कोई खर्च अपेक्षित नहीं है। इस विधेयक के कारण लगभग 140 करोड़ रुपये की वार्षिक हानि अनुमानित है।

प्रत्यायोजन विधान से संबंधी ज्ञापन

मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2012 में अधीनस्थ विधान बनाने के लिये किसी अधिकारी को शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं रखा गया है।

पी. एन. मिश्रा, सचिव

No. 21(11)/2012/LAS-IV/Leg./4309.—The following is published for general information.—

THE DELHI VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) BILL, 2012

(Bill No. 11 OF 2012)

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 5th June, 2012)

A Bill further to amend Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in Section 2, in sub-section (1), in clause (zd), after sub-clause (vii), before the Explanation occurring at the end thereof, the following provisos shall be inserted, namely :

"PROVIDED that an amount equal to the increase in the price of petrol (including the duties and levies charged thereon by the Central Government) taking effect from the 3rd June, 2012 shall not form part of the sale price of petrol sold on or after the date of the commencement of the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012 till such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, direct or if the price of petrol falls below the sale price prior to 3rd June, 2012, whichever is earlier.

PROVIDED further that if the price of petrol further increases from the level of price as on 3rd June, 2012, the aforesaid proviso shall not have any effect on such further increase:

PROVIDED also that if the price of petrol declines but remains above the price prevailing prior to 3rd June, 2012, the aforesaid proviso shall have effect to the extent of the remaining increase:

PROVIDED also that the aforesaid proviso shall not take effect till the benefit is passed on to the consumers."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendment of Section 2 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 is proposed to give some relief to the general public from the high increase in the price of petrol by way of exemption of levy of VAT on the increased price of petrol which has been effected from 3rd June, 2012.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

(SHEILA DIKSHIT)

Chief Minister/Finance Minister

New Delhi

Dated :

FINANCIAL MEMORANDUM

The Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2012 does not involve any additional financial implications since no outgo on new posts is anticipated from the Consolidation Fund of the National Capital Territory of Delhi. An annual loss to the tune of Rs. 140 crores is estimated on account of this Bill.

2031 DG/12-3

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Bill, 2012 does not make provision for the delegation of power in favour of any functionaries to make subordinate legislation.

P. N. MISHRA, Secy.

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 5 जून, 2012

सं. फा. 03(11)/वित्त(क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएस-III/434.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के छंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमति/कु.)	पदनाम
1	अजित श्रीवास्तव, आईएएस	विशेष आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 5th June, 2012

No. F. 3(11)/Fin.(T&E)/2009-10/DS-III/434.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1	Sh. Ajit Srivastava, IAS	Special Commissioner of Value Added Tax

सं. फा. 03(9)/वित्त(क. एवं स्थाप.)/2009-10/पार्ट-1/डीएस-III/433.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के छंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमति/कु.)	जन्म तिथि	पदनाम
1	सतिन्दर मलिक	23-02-73	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2	अजय कुमार अरोड़ा	27-09-73	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. कामरा, उप-सचिव-III वित्त

No. F. 3(9)/Fin.(T&E)/2009-10/Ptf.-I/DS-III/433.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following Officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	DOB	Appointed As
1	Satinder Malik	23-02-73	Assistant Value Added Tax Officer
2	Ajay Kumar Arora	27-09-73	Assistant Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. KAMRA, Dy. Secy. -III (Finance)